declared an essential commodity like cement so that its distribution and price will be controlled and once its price is fixed, nobody will be allowed to sell it at a price higher than the fixed price? That leads to my second question. In 1978, you have said, the prices were Rs. 3,600. I find from your statement that import was not banned. Import was allowed even when the Janata Government was in power. I would like to know whether import was banned. If not, the other question is, the prices, as you have said, have come down from Rs. 3,600 to Rs. 2,100 to Rs. 2,400 this year. But the prices had gone down to Rs. 1,100 in November 1980. I would like to know what price the Department considers as a reasonable price at which soda ash should be made available to the consumers. It is no use saying that the prices have come down. What is the actual cost and what profitability should be there? Therefore, the time has come for fixing a price, say Rs. 500 or Rs. 600, or whatever price is considered reasonable. So I would like to know whether the price of Rs. 2100 at which it is selling, is a reasonable price for the consumers—this soda ash. Thirdly, what are the reasons for these accumulated stocks? The policy of the Government is to export or import. Are there any countries where soda ash is much costlier than in India? Have you considered any other market outside India which is costlier than in India so that soda ash can be exported? Lastly, why is this not done through the State Trading Corporation or any other public corporation? Why is it left to the industrialists?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That was already replied to. It is under discussion.

SHRI P. C. SETHI: I do not agree that the policy which was envisaged of free mechanism of control and distribution, has failed. As far as OG and imports are concerned, they were allowed from January 1979. Before that there were no imports. It would not be desirable to impose a price control order, a statutory control order. My experience with regard to diesel oil has shown that when we were using it as a controlled commodity, it was in scarcity and since we lifted the control, diesel is available in plenty. However, we are watching the situation. The question of statutory control does not arise at present. We are monitoring the distribution as far as the industry is concerned. Other requirements of the small consumers are also being monitored and we will take care to see that indigenous production and imports...

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: What about the price of soda ash? Is it reasonable? You have said it has declined from Rs. 2100...

SHRI P. C. SETHI: With regard to this I have said in reply to Dr. Bhai Mahavir's question that this of engaging the services of BICP, for going into the cost structure is receiving our attention and if the price structure is looked into by the BICP, we would certainly take necessary steps.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now we take up Special Mentions.

REFERENCE TO THE REPORTED COLD WAVE DEATHS IN BIHAR

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह देश के लिये कितने शर्म की बात है कि आजाद भारत में आज भी लोग शहरों के अन्दर और गांवों के अन्दर वस्त्र के बिना जाड़े में ठिठुर कर मर रहे हैं। अब तक जो

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

अखबारों में रिपोर्ट आयी है उन रिपोर्टों के मुताबिक केवल बिहार में कोई सौ से अधिक आदमी जाड़े से मर चुके हैं और संपूर्ण देश में कितने लोग मरे हैं इस का हिसाब लगाया जाय तो कोई दो सौ, चार सौ, पांच सौ या हजार आदमी तो जरूर मर चुके होंगे। और जगह की बात तो जाने दीजिए, यह दिल्ली शहर में जहां तक कि सब कुछ है और जिसको सजाने पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, उस में भी अगर आप निकल जायें तो रात में आप फुटपाथ पर देखेंगे कि सैकड़ों आदमी बिना वस्त्र के पड़े हुए हैं जो ठिठुर रहे हैं। उन के पास कोई वस्त्र नहीं है। तो इस देश में अगर भर पेट भोजन न मिले तो न मिले, अगर आप लोगों को मकान नहीं दे सकते तो न दे सकें, लेकिन जाड़े में कपड़े के बिना जो लोग ठिठुर कर मर रहे हैं उन के लिए सरकार की ओर से कोई कार्यवाही न किया जाना और दूसरी तरफ हम लोग यहां हैं और दूसरे जो बड़े-बड़े लोग हैं उन के लिए आप सब तरह की सुविधायें देते रहते हैं, वे लोग बिजली से सारे मकान को गर्म कर के बैठते हैं और मकानों में गर्म कपड़े पहन कर बैठते हैं और दूसरी तरफ हजारों लोग ठिठुर कर मरते हैं तो यह आजाद भारत के लिए बड़े शर्म की बात है। दुनिया में ऐसा देखने को और कहीं नहीं मिला होगा कि जहां अन्न और वस्त्र के बिना लोग मरते हों। दूसरे देशों में इंसानों को इतना जरूर मिल जाता है। लेकिन जहां तक तमाम मरने वाले लोग हैं अखबारों में जो रिपोर्ट आती हैं, इतने मर गये, तो अगर अखबारों के रिपोर्टर्स ने कहीं देख लिया तो उस की खबर आ जाती है नहीं तो कोई खबर नहीं आती है। लेकिन आज हजारों लोग उत्तर प्रदेश में, उत्तर बिहार में हैं जहां आप चले जाइये तो देखेंगे कि वहां हजारों लोग ऐसे हैं कि जो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। उन को अपनी देह ढकने के लिए 5 गज कपड़ा भी नहीं मिल रहा है। मरने के बाद कफन न मिले तो न सही, लेकिन जिन्दा इंसान को ओढ़ने के लिए 5 गज कपड़ा भी नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आज सरकार की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। इस लिए मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दुनियां की नजरों में और लोगों की नजरों में यह देश कितना नीचा हो रहा है, कितने आप गिरे हुए हैं इस की ओर भी कम से कम हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जाड़े से मरने वाले गरीबों के लिए सरकार की ओर से कोई न कोई इंतजाम जरूर होना चाहिए, आजाद भारत में यह जरूर होना चाहिए कि इस देश में कोई भी आदमी जाड़े के दिनों में कपड़े के बिना मरने न पावे। यह जिन्दगी का सवाल है, यह मानवता का सवाल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हर दिन अखबारों में रिपोर्टे निकलती हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वह इस ओर सरकार का और लोगों का ध्यान दिलाते हैं, नहीं तो सरकार की ओर से कभी कोई छानबीन ही नहीं की जाती है और कौन मर रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। कम से कम आप दिल्ली में ही देख लीजिए। ज्यादातर मरने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग होते हैं।

श्री उपसभापति : रात को नहीं जाते हैं देखने ?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : वे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी की तलाश में यहां ठिठुर-ठिठुर कर मरते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री उपसभापति : बहुत इम्पार्टेंट बात है।